(v) Cooperation of people in protection and management of forests is through Joint Forest management practices.

उर्वरक क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विलम्ब

*278. **श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी :**
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या रसायन और उवर्रक क्षेत्र में करोड़ो रूपये की लागत वाली लगभग बीस परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं;

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र में करोंड़ो रूपये की लागत वाली लगभग बीस परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इनके कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कार्यान्वयन में विलम्ब के संदर्भे में कोई आकलन किया हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं?

रसायन और उवर्रक मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औघोगिक नीति संकल्प के अनुसार नई उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिये किसी लाइसेंस की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है। तथापि,उर्वरक विभाग के प्रशसनिक नियंत्रणाधीन सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को निदेशक मण्डल को प्रदत्त अधिकारों से परे पूंजी व्यय करने से पूर्व सरकार का अनुमोदन लेना पड़ता हैं।

इस समय, सार्वजानिक/सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन एकमात्र प्रमुख उर्वरक परियोजना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को आपरेटिव लिमिटेड (इफ्क्रो) की काण्डला विस्तार परियोजना हैं। इस परियोजना में 212.20 करोड़ रूपए की अनुमाति लागत से प्रतिवर्ष एन पी के की 3.70 लाख टन और डी ए पी की 2.27 लाख टन अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई है।इस परियोजना की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 22.10.99 तक आरम्भ हो जाने की आशा की जाती हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

National Culture Policy

*279. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the National Culture Policy;

(b) if not, the steps Government propose to take to expedite its finalisation;

(c) whether Government are aware that in the absence of such a policy, cultural values of the nation are getting eroded; and

(d) the measures Government propose to take to safeguard the unique cultural values of India?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) The National Policy on Culture is under the consideration of the Government.

(c) and (d) Cultural values are rooted in the history and heritage of our country. The Policy, as and when it is enunciated, will be a further articulation of these values. The Government is already attempting to foster cultural values through its various schemes and autonomous institutions established. The National Education Policy 1986 (as updated in 1992) and its Programme of Action lay emphasis on incorporating the cultural perspective in the content and process of education.

Medication Scheme for Needy Patients

*280. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Indian Medical Association General Secretary as reported in the Times of India, New Delhi dated 27th May, 1998 to the effect that 83 per cent patients in the country are treated in private sector hospitals and nursing homes but there is no way in which a person in need of medical treatment can meet high cost of treatment;

(b) whether Government propose to start any effective medication scheme to enable needy patients to meet high cost of medicare;

(c) if so, by when; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) With reference to the news item, it is stated that a Household Survey of Health Care Utilization and Expenditure carried out by the National Council of Applied Economic Research (NARER) in 1993 showed that 62% of the cases in rural areas and 60% of the cases in urban areas, inpatient treatment was sought in public sector hospitals. However, about 52% in rural areas and 59% in the urban areas sought ambulatory care in private sector facilities. For providing generally free health care services, there are an estimated 4579 hospitals at the district and sub-district levels accounting for about 65% of the total beds in the country established in the public sector. A National Illness Assistance Fund has been recommended to be set up by the State Governments to enable financial assistance to be given to patients, below the poverty line, suffering from life threatening diseases.

Health being a state subject under the Constitution, the provision of health services is the responsibility of the State Governments. Central Government continues to support the State Governments in controlling specific diseases through the implementation of National Disease Control Programmes under which treatment is extended free of charge.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक संयंत्रे के विस्तार का लक्ष्य

1974. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस संबंध मं लक्ष्य प्राप्ति की तथ्यात्मक स्थिति क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित आकलन भी किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु यूरिया की उत्पादन वृद्वि के लिए अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए के पटेल) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सार्वजानिक/सहकारी क्षेत्र में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) की विजयपुर तथा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर काआपरेटिव लि. (इफ्को) के आवंला स्थित उर्वरक संयंत्रों के विस्तार की परिकल्पना की गई थी। इन संयंत्रों की क्षमता दुगुने होने के परिणामस्वरूप 2026 करोड़ रूपए की कुल लागत पर यूरिया की क्षमता में 14.52 लाख मी. टन प्रतिवर्ष की वृद्वि हुई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान उर्वरक पोषकों के उत्पादन का अनुमान 111.55 लाख मी. टन लगाया गया हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने हेतु 23.28 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया गया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 7.26 लाख मी. टन के वार्षिक क्षमता वाले ग्रास-रूट यूरिया संयंत्र के लिए लगभग 1570 करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता हैं।

मंत्री जी के व्यक्तिगत स्टाफ का संसद सदस्यों के साथ व्यवहार

1975. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी स्टाफ और अतिरिक्त निजि सचिव द्वारा अपने अशोभनीय व्यवहार से संसद सदस्यो की गारिमा को ठेस पहुंचाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होने सांसदों की गरिमा को बरकरार रखने के लिए राज्य मंत्री को कोई निर्देश दिया हैं;

(ग) क्या उन्होने इस संबंध में दोषी पाए गए अतिरिक्त निजी सचिव और स्टाफ को बदलने के लिए राज्य मंत्री को आदेश जारी किए है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) वैयक्तिक कर्मचारियों को सभी के साथ, खासतौर से माननीय संसद सदस्यों और